

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 | संख्या 294 | श्री विजयपुरम, मंगलवार, 03 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए





डॉ. दिनेश शर्मा जी, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, ने आज लोक निवास, श्री विजयपुरम में दिल्ली दौरे से पूर्व मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, पुलिस महानिदेशक श्री रविन्दर सिंह यादव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में माननीय उप राज्यपाल महोदय ने कानून–व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने, पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करने तथा दीपावली पर्व के दृष्टिगत समस्त नागरिक सुविधाओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 99 लाभार्थियों के दावों के निपटान हेतु 23.16 लाख रुपये की मंजूरी दी

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) की अध्यक्षा एवं श्रम एवं रोज़गार सचिव श्रीमती वंदना राव, भा.प्र.से., ने आज श्रम आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बोर्ड की 34वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र सरकार के नामित प्रतिनिधि, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के प्रतिनिधि, नियोजकों तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। अध्यक्ष ने सभी पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी लाभों का प्रभावी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

कार्यसूची के विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श के बाद बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत पात्र लाभार्थी श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत 99 दावों के निपटान हेतु 23.16 लाख रुपये जारी करने की सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की। इनमें पेंशन लाभ, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता एवं मृत्यु सहायता शामिल हैं।



प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड ने पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्वीकृत वित्तीय सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से करने का भी निर्णय लिया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 2009 में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में बोर्ड पंजीकृत लाभार्थियों के लिए नौ कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है।

आरएएमपी योजना के तहत फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी में आठ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न





श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग ने भारतीय फोटोग्राफी संस्थान (आईआईपी), नोएडा के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने एवं गति प्रदान करने की योजना (आरएएमपी) के अंतर्गत आयोजित आठ दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2026 तक श्री विजयपुरम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप रचनात्मक एवं तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था।

इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन इमेजिंग, कैमरा संचालन एवं पोस्ट–प्रोडक्शन सहित दृश्य कला और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को जल के भीतर फोटोग्राफी तथा खगोलीय फोटोग्राफी जैसे विशेष क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन आईआईपी, नोएडा की विशेषज्ञ प्रशिक्षक सुश्री गरिमा चौधरी एवं श्री आसिफ खान ने किया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए पर्यटन निदेशक सुश्री आकांक्षा सिंह, भा.प्र.से., ने प्रशिक्षुओं को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन की अपार संभावनाओं से अवगत कराया तथा बताया कि फोटोग्राफी आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। उन्होंने जानकारी दी कि आरएएमपी योजना के

शेष पृष्ठ 4 पर

लाइट अप रेगाटा–2026 का आयोजन, रोशनी से जगमगाती नौकाओं ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध





श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

अण्डमान निकोबार सेलिंग क्लब (एएनएससी) द्वारा नौकायन की भावना का उत्सव मनाने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के युवा नौकायन प्रेमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाइट अप रेगाटा–2026 का आयोजन किया गया। यह आयोजन अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत युवा नौकायन प्रतिभागियों के लिए नौकायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें अपने नौकायन कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की निदेशक (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन) सुश्री आकांक्षा सिंह, भा.प्र.से., ने विजेताओं को ट्रॉफियां तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान कर उनकी

शेष पृष्ठ 4 पर

आरएएमपी योजना के तहत प्रशिक्षुओं को खगोलीय फोटोग्राफी का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान



श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

विश्व बैंक की सहायता से संचालित आरएएमपी योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा फोटोग्राफी एवं कैमरा संचालन पर आयोजित आठ दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम के तहत 1 नवंबर को प्रशिक्षुओं को तेजी से उभरते विशिष्ट क्षेत्र खगोलीय फोटोग्राफी (एस्ट्रो–फोटोग्राफी) का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया।

1 नवंबर की रात्रि में आयोजित क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं को चिड़ियाटापू स्थित व्हिसलिंग वुड्स ले जाया गया, जहां उन्हें रात्रि में लंबी अवधि के एक्सपोजर के माध्यम से फोटोग्राफी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान साफ रात्रि आकाश में आकाशगंगा, तारों की गति से बनने वाली प्रकाश रेखाओं तथा विभिन्न तारामंडलों की तस्वीरें लेने की तकनीक सिखाई गई।

प्रशिक्षुओं के साथ आयोजित संवादात्मक सत्र में प्रमुख खगोलीय संचारक श्री उदय भास्कर ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खगोलीय पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि खगोलीय फोटोग्राफी एक अत्यंत विशिष्ट एवं अभी तक कम विकसित क्षेत्र है, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रमाणित विशेषज्ञों की संख्या नगण्य है, जबकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को खगोलीय पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए आरएएमपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में भी जानकारी दी। इस योजना के तहत खगोलीय दूरबीनों की खरीद एवं स्थापना के लिए निम्नलिखित अनुदान उपलब्ध कराया जाता है:

- पुरुष लाभार्थियों के लिए : दूरबीन की खरीद एवं स्थापना सहित कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- महिला एवं जनजातीय लाभार्थियों के लिए : समावेशी लघु उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दूरबीन की खरीद एवं स्थापना सहित कुल लागत का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षुओं को पर्यटन के इस विशिष्ट क्षेत्र को विकसित करने के लिए वर्तमान में प्रशासन द्वारा की जा रही सक्रिय पहलों से भी अवगत कराया गया।

दीपावली मेले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री 4.30 लाख रुपये के पार

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

ग्रामीण विकास निदेशालय के तत्वावधान में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ग्रामीण आजीविका मिशन (एएनआईआरएलएम) के अंतर्गत समर्थित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मरीना पार्क में आयोजित दीपावली मेले में लगभग 4.30 लाख रुपये का उत्साहजनक बिक्री कारोबार दर्ज़ किया गया। इस मेले

शेष पृष्ठ 4 पर

सीपीघाट ग्राम पंचायत में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान की सीपीघाट ग्राम पंचायत ने उद्योग निदेशालय के सहयोग से आज ग्राम पंचायत भवन में आयोजित 15 दिवसीय व्यापक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्यों सहित स्थानीय 15 महिलाओं एवं अन्य सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें स्वरोज़गार एवं स्थानीय स्तर पर लघु उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से व्यावहारिक व्यावसायिक कौशल सिखाए गए।



समापन समारोह को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती ज्योति राज ने दो सप्ताह तक चले इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं के समर्पण और सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उद्योग निदेशालय के प्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा समुदाय के सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षुओं ने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है तथा वे स्वयं के आय अर्जित करने वाले लघु उद्यम शुरू करने के लिए अधिक सक्षम और तैयार महसूस कर रही हैं।

द्वीपों में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से पहली बछिया का जन्म

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

अण्डमान–निकोबार प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने पशुधन विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। द्वीपसमूह में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक (ईटीटी) के माध्यम से उत्पन्न पहली मादा बछिया का जन्म हुआ है। इस बछिया का जन्म 1 नवंबर, 2026 को गाराचरामा स्थित पशु चिकित्सालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कामराज नगर निवासी श्रीमती के. प्रिया की गाय से हुआ। गाय और नवजात बछिया दोनों स्वस्थ हैं तथा प्रसव सामान्य रूप से हुआ।



भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रक्रिया 10 फरवरी, 2026 को संपन्न की गई थी तथा 20 मार्च, 2026 को गर्भधारण की पुष्टि हुई थी। बछिया का वजन उसकी छाती की परिधि ा और लंबाई के माप के आधार पर 21.3 किलोग्राम आंका गया है। यह सफल जन्म द्वीपसमूह में इस वर्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) डेयरी सर्विसेज के सहयोग से शुरू की गई भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना के प्रथम चक्र की सफलता का प्रतीक है।

भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक परियोजना का उद्देश्य स्थानीय गायों की आनुवंशिक गुणवत्ता में तेजी से सुधार करना, मादा बछड़ों के जन्म का अनुपात बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना तथा केंद्रशासित प्रदेश में डेयरी विकास को गति प्रदान करना है। फरवरी, 2026 में दक्षिण अण्डमान के चयनित क्षेत्रों से इस तकनीक के माध्यम से भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली मादा बछिया का जन्म द्वीपों की परिस्थितियों में इस उन्नत तकनीक की सफलता का महत्वपूर्ण प्रमाण है तथा इससे प्रजनन संबंधी आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने इस सफल प्रत्यारोपण, गर्भावस्था की निगरानी तथा प्रसव प्रक्रिया में शामिल लाभार्थी पशुपालक और पशु चिकित्सा दल को बधाई दी है। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस उपलब्धि से अधिकाधिक पशुपालक वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों, विशेषकर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक और लिंग–चयनित वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमेन) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ पशुपालकों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

खेलो इंडिया युवा खेल–2026 में वाइल्ड कार्ड प्रवेश के लिए पात्र खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य निदेशालय ने तेलंगाना में 11 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल (केआईवाईजी)–2026 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का प्रतिनिधित्व करने हेतु वाइल्ड कार्ड प्रवेश के लिए 18 वर्ष से कम आयु (यू–18) के इच्छुक एवं पात्र बालक–बालिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए निम्नलिखित खेल विधाओं में आवेदन किए जा सकते हैं :

1. तीरंदाजी, 2. एथलेटिक्स, 3. बैडमिंटन, 4. मुक्केबाजी, 5. साइकिलिंग, 6. जिम्नास्टिक, 7. जूडो, 8. निशानेबाजी, 9. तैराकी
10. टेबल टेनिस, 11. टेनिस, 12. थांग–ता, 13. भारोत्तोलन, 14. कुश्ती, 15. योगासन।

भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से प्राप्त आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों का चयन वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 के दौरान आयोजित मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

यह उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया युवा खेल–2026 की निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार, निदेशालय को प्राप्त आवेदनों में से सर्वश्रेष्ठ दो बालकों एवं दो बालिकाओं के नाम वाइल्ड कार्ड मूल्यांकन समिति (डब्ल्यूसीईसी), खेलो इंडिया युवा खेल–2026 के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुशंसित खिलाड़ियों के नाम इसके बाद खेलो इंडिया युवा खेल–2026 में भागीदारी के लिए नामांकित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी पात्र खिलाड़ियों की जानकारी के लिए चयनित नामों की सूचना प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विधिवत प्रकाशित की जाएगी।

पात्रता संबंधी मानदंड :

1. खेलो इंडिया युवा खेल–2026 में भाग लेने के लिए खिलाड़ी का जन्म 1 जनवरी, 2009 को या उसके बाद होना अनिवार्य है। अर्थात खिलाड़ी की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. खिलाड़ी की आयु के सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई दो दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :
   (क) आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट
   (ख) मैट्रिक प्रमाण–पत्र
   (ग) जन्म प्रमाण–पत्र (नगरपालिका/ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम पांच वर्ष पूर्व अर्थात 1 जनवरी, 2021 को या उससे पहले जारी किया गया हो)।
3. किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने की पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :
   (क) राज्य का अधिवास प्रमाण–पत्र
   (ख) पासपोर्ट
   (ग) पदस्थापन/कार्यस्थल/विद्यालय का वास्तविक प्रमाण–पत्र।

इच्छुक एवं पात्र खिलाड़ी अपने आवेदन संबंधित क्षेत्र के सहायक पर्यवेक्षक (खेल) के पास 10 नवंबर, 2026 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–क) में पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा आवेदक के हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। इसके साथ वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 के दौरान आयोजित मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एवं ज़िला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त खेल उपलब्धियों के स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारी के समर्थन में सभी संबंधित दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियां भी जमा करनी होंगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आवेदन प्रारूप (अनुलग्नक–क) खेल विभाग के पोर्टल **https://sports.andamannicobar.gov.in** तथा अण्डमान तथा निकोबार केंद्रशासित प्रदेश के पोर्टल **https://andamannicobar.gov.in** पर उपलब्ध है।

नैदानिक अनुसंधान इकाई (होम्योपैथी) ने आयोजित किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 7.0 के अंतर्गत प्लॉग रन व वॉक

श्री विजयपुरम, 2 नवम्बर।

नैदानिक अनुसंधान इकाई (होम्योपैथी), श्री विजयपुरम द्वारा 30 अक्टूबर, 2026 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 7.0 के अंतर्गत प्लॉग रन व वॉक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इकाई के प्रभारी अधिकारी डॉ. शांति अधिकारी तथा सभी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।



प्लॉग रन व वॉक का शुभारंभ श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक फ्लैग पॉइंट से हुआ। प्रतिभागियों ने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय की। शारीरिक फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देते हुए, प्रतिभागियों ने मार्ग में बिखरे कचरे को एकत्र किया। इस गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने तथा कचरे के उचित निपटान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अभियान का प्रेरणादायक संदेश "फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज" है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने तथा स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्यों के अनुरूप शारीरिक फिटनेस, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रति नैदानिक अनुसंधान इकाई (होम्योपैथी), श्री विजयपुरम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

70वीं एसजीएफआई राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

शिक्षा निदेशालय द्वारा 11 से 20 दिसंबर तक श्री विजयपुरम में 70वीं एसजीएफआई राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता (बालक अंडर–19) का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा एक स्मारिका का विमोचन किया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के अधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के फुटबॉल प्रेमियों से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से संबंधित फुटबॉल, अन्य प्रमुख खेलों एवं खेल गतिविधियों पर लेख भेजने का अनुरोध किया गया है।

लेख 100 शब्दों से कम होने चाहिए तथा 20 नवंबर तक शिक्षा निदेशालय के खेल अनुभाग में ई–मेल **sportsectionpb@gmail.com** के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दूरभाष संख्या **9434263798** पर संपर्क किया जा सकता है।

दीपावली मेले में स्वयं सहायता समूहों ——————————पृष्ठ 1 का शेष

ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता एवं बाज़ार में उनकी स्वीकार्यता को प्रदर्शित किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार तीन दिनों की अल्प अवधि में हुई उत्साहजनक बिक्री ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बढ़ती पहचान को दर्शाती है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदर्शनियों, मेलों, संस्थागत खरीद, खुदरा बिक्री केंद्रों तथा अन्य प्रचार गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को लगातार बाज़ार तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। मिशन का उद्देश्य इन बाज़ार संपर्कों को और सुदृढ़ करना तथा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों के



रूप में बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से 'लखपति दीदी' की परिकल्पना को साकार करने तथा ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को स्थायी रूप से सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया जा रहा है।

आरएएमपी योजना के तहत फोटोग्राफी ——————————पृष्ठ 1 का शेष

अंतर्गत विभाग स्थानीय समुदायों की रोज़गार क्षमता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा।

कार्यक्रम के विस्तार के संबंध में सुश्री आकांक्षा सिंह ने बताया कि द्वीपसमूह के विभिन्न स्थानों, जिनमें स्वराज द्वीप एवं शहीद द्वीप शामिल हैं, में भी फोटोग्राफी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, निदेशक ने आरएएमपी योजना के अंतर्गत आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि इनमें होमस्टे संचालन, पाक कला, व्यावसायिक रसोइया प्रशिक्षण, टैक्सी संचालन तथा नौका एवं साहसिक खेलों के प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे। उन्होंने युवाओं को अपने कौशल को उन्नत बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं से यह भी अनुरोध किया कि वे इन कार्यक्रमों की जानकारी अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से वंचित रहने वाले लोग भी इन सरकारी अवसरों का लाभ उठा सकें। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आठ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित किए जाने के साथ समापन सत्र संपन्न हुआ।

लाइट अप रेगाटा–2026 का आयोजन ——————————पृष्ठ 1 का शेष

उपलब्धियों को सम्मानित किया और उन्हें नौकायन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रोशनी से सजी नौकाओं का शानदार प्रदर्शन रहा। इस दौरान सुंदर रंग–बिरंगी रोशनी से सजी नौकाओं ने श्री विजयपुरम के मरीना पार्क एवं फ्लैग पॉइंट के समीप समुद्री जलक्षेत्र में नौकायन किया। समुद्र की लहरों पर प्रतिबिंबित होती रंग–बिरंगी रोशनी ने एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य जल क्रीड़ा के रूप में नौकायन को बढ़ावा देना, युवा नौकायन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा नौकायन एवं समुद्री मनोरंजन गतिविधियों के प्रमुख गंतव्य के रूप में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की संभावनाओं को प्रदर्शित करना था।

तालाब आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली पर प्रशिक्षण संचालित

श्री विजयपुरम, 2 नवंबर।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–कृषि विज्ञान केंद्र (आईसीएआर–केवीके), नींबूडेरा, मध्य अण्डमान द्वारा खेत बचाओ अभियान (केबीए)–रबी 2026 के अंतर्गत 29 से 31 अक्टूबर, 2026 तक ड्यूक नगर, स्वदेश नगर ग्राम पंचायत में किसानों एवं महिला किसानों के लिए "तालाब आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जलीय कृषि को फसल उत्पादन एवं पशुपालन गतिविधियों के साथ एकीकृत कर टिकाऊ एवं विविधीकृत कृषि को बढ़ावा देना था। इसमें कृषि संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि अपशिष्टों के पुनर्चक्रण, उत्पादकता में वृद्धि, कृषि आय में बढ़ोतरी तथा आजीविका के बेहतर अवसरों पर विशेष ज़ोर दिया गया।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आईसीएआर–केवीके, नींबूडेरा के विषय वस्तु विशेषज्ञ (मत्स्यिकी) श्री सुबम देबरॉय ने तालाब आधारित एकीकृत कृषि प्रणालियों की वैज्ञानिक योजना एवं प्रबंधन पर तकनीकी सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में उपयुक्त मछली प्रजातियों का चयन, तालाब की तैयारी, जल गुणवत्ता प्रबंधन, पशुधन एवं मत्स्य पालन का एकीकरण तथा मछलियों के स्वास्थ्य प्रबंधन सहित रोगों की रोकथाम पर विशेष ज़ोर दिया गया।

विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) डॉ. राकेश दावर ने ध्यान की खेती, बागवानी फसलों एवं मसाला उत्पादन को एकीकृत कर तालाब आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली में विविधता लाने पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। उन्होंने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कृषि आय में बढ़ोतरी तथा टिकाऊ आजीविका के लिए विभिन्न कृषि गतिविधियों के एकीकरण पर ज़ोर दिया।



विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि अभियांत्रिकी) डॉ. मनोज कुमार ने तालाब आधारित एकीकृत कृषि प्रणालियों की रूपरेखा एवं निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने उचित कृषि भूमि विन्यास एवं आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया।

मत्स्य उप–केन्द्र, बिलिग्राउंड के मत्स्य निरीक्षक श्री संजीब सूत्रधार ने तालाब आधारित एकीकृत कृषि प्रणालियों में वैज्ञानिक मछली आहार एवं आहार प्रबंधन पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को मत्स्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सहायता कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीएआर–केवीके, नींबूडेरा के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी प्रमुख डॉ. वाई. रामकृष्ण तथा आईसीएआर–सीआईएआरआई, श्री विजयपुरम के कार्यवाहक निदेशक डॉ. जय सुंदर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 25 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

1 नवम्बर से बदल गए पैसों से जुड़े ये नियम, कहीं बढ़ेगा खर्च तो कहीं मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली, 02 नवम्बर।

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, बैंकिंग, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं। इनका असर कारोबारियों, पेंशनभोगियों, मोबाइल उपभोक्ताओं और निवेशकों पर पड़ने वाला है। कहीं जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होगी, तो कहीं क्रेडिट कार्ड से बिल भरना महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कैंसर मरीजों को भी इस महीने दवाओं की कीमतों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।



नए नियमों के तहत अब कारोबारी को–वर्किंग स्पेस यानी साझा ऑफिस के पते पर भी जीएसटी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें को–वर्किंग स्पेस की सदस्यता से जुड़ा दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसमें कारोबारी का पता स्पष्ट होना जरूरी है।

इसके अलावा बिजली बिल और हाउस टैक्स जैसे दस्तावेज भी पते के प्रमाण के तौर पर देने होंगे। आधार आधारित सत्यापन पूरा होने पर सामान्य परिस्थितियों में अधिकारी को पते की भौतिक जांच के लिए नहीं जाना होगा। हालांकि, धोखाधड़ी या किसी गंभीर गड़बड़ी का संदेह होने पर जांच की जा सकती है। इससे छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप को राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकारी पेंशन लेने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनभोगियों के लिए नवंबर का महीना जरूरी है। उन्हें 1 से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।

पेंशनभोगी बैंक जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी जमा किया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब यूटिलिटी बिल भुगतान पर ध्यान देना होगा। नए नियम के मुताबिक, 50 हजार रुपये से अधिक के बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट बिल के भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यह शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम 2,000 रुपये तक होगा। पहले इस तरह के भुगतान पर बैंक की ओर से यह शुल्क नहीं लिया जाता था। ऐसे में अधिक राशि के बिल क्रेडिट कार्ड से चुकाने वालों का खर्च बढ़ सकता है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी बदलाव किया गया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब क्पतमबज च्संद डिफॉल्ट विकल्प के रूप में दिखेगा। इसका फायदा उन निवेशकों को मिल सकता है, जो बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे निवेश करना चाहते हैं। वहीं, अगर निवेशक Regular Plan चुनते हैं, तो उन्हें पहले उसके एक्सपेंस रेश्यो और अतिरिक्त लागत की जानकारी दी जाएगी। इससे निवेश करने से पहले दोनों योजनाओं के खर्च की तुलना करना आसान होगा।

सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी नवंबर में अहम मौका आने वाला है। Sovereign Gold Bond की कुछ सीरीज के निवेशक तय तारीखों पर समय से पहले अपना पैसा निकाल सकेंगे।

नवंबर के इन बदलावों में कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण में आसानी, पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा और कैंसर मरीजों को दवाओं की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, PNB क्रेडिट कार्ड से अधिक राशि के यूटिलिटी बिल का भुगतान करने वालों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इन बदलावों की जानकारी रखें और अपने बैंक, पेंशन तथा निवेश से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरे करें।

केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2026 की घोषणा, देशभर के 490 पुलिसकर्मी और अधिकारी होंगे सम्मानित

नई दिल्ली, 02 नवम्बर (हि.स.)।

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' की घोषणा कर दी है। इस वर्ष देशभर के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के कुल 490 अधिकारियों और जवानों को इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, यह सम्मान पुलिसिंग, जांच, खुफिया सेवा और फोरेंसिक विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और जांच एजेंसियों में बेहतर कार्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना और उत्कृष्ट सेवाओं को पहचान देना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक फरवरी, 2024 को जारी अधिसूचना के माध्यम से 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' की स्थापना की थी। इस पुरस्कार के तहत पुलिस और सुरक्षा संगठनों में असाधारण प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इसमें राज्य पुलिस बलों, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, विशेष खुफिया शाखाओं, केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और असम राइफल्स के अधिकारी एवं जवान शामिल हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पहला पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न अभियानों में असाधारण प्रदर्शन और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए। दूसरा गंभीर और जटिल मामलों की जांच में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए। तीसरा केंद्रीय



और राज्य स्तर पर अदम्य साहस, समर्पण और उत्कृष्ट खुफिया कार्य करने वाले कर्मियों के लिए और चौथा केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सरकारी वैज्ञानिकों को दिया जाता है।

इस पदक की घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस सम्मान के जरिए उन अधिकारियों और जवानों के योगदान को पहचान दी जाती है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक का उद्देश्य पुलिस और सुरक्षा संगठनों में उच्च पेशेवर मानकों को प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना और अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है।

क्वाड देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली, 02 नवम्बर।

अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की कल अमरीका के अटलांटा में बैठक हुई। बैठक में क्वाड की चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, स्वतंत्र और खुले हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और जरूरी सामान की आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने व्यापार पर मनमाने प्रतिबंधों और आपूर्ति में रुकावट पैदा करने वाली नीतियों पर चिंता जताई। मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब–अल–मंडेब जलडमरूमध्य में समुद्री रास्तों को सुरक्षित और खुला रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में एआई के महत्व पर भी चर्चा हुई। क्वाड देशों ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देने के लिए आठ करोड़ 50 लाख डॉलर से अधिक की तकनीकी और आर्थिक मदद देने की मंशा जताई।

मंत्रियों ने ऑनलाइन और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों की तस्करी करने और



उनसे जबरन साइबर ठगी कराने वाले गिरोहों की निंदा की। बैठक में नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। मंत्रियों ने बचाव कार्यों में भारत की भूमिका और नेपाल को सभी क्वाड देशों की ओर से दी गई मदद का भी उल्लेख किया। क्वाड देशों के मंत्रियों ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और विकास से जुड़ी योजनाओं में हुई प्रगति का स्वागत किया।

वीबी–जी राम जी अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम अधिसूचित

नई दिल्ली, 02 नवम्बर (हि.स.)।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी–जी राम जी) अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम–2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। अब इससे जुड़ी शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर हो सकेगा।

मंत्रालय के अनुसार नए नियम के तहत राज्य सरकारों की ओर से ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तर पर इसकी पूरी निगरानी जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर की जाएगी। आम नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से, डिलीवरी प्रमाण वाले स्पीड पोस्ट, निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीफोन–हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑफलाइन प्राप्त शिकायतों को उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को तुरंत डिजिटल दस्तावेज दी जाएगी।

इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था स्थापित करना है। इसके अलावा शिकायत निवारण अधिकारी को 7 कार्य दिवसों के भीतर मामले की जांच पूरी करनी होगी और 15 दिनों के भीतर शिकायत का अंतिम निपटारा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। शिकायतों के पंजीकरण से लेकर निपटारे तक पूरी प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। यदि 15 दिनों के भीतर किसी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो वह स्वतः ही राज्य सरकार की ओर से स्थापित व्यवस्था के तहत अगले उच्च स्तर के प्राधिकारी के पास भेज दी जाएगी। पारित आदेशों के विरुद्ध वीबी–जी राम जी अधिनियम की अनुसूची–I के अनुसार अपील दायर करने और उसके निस्तारण की सुविधा भी दी गई है।

मंत्रालय के मुताबिक यह नई अधिसूचना ग्रामीण परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने तथा प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी नागरिक को प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण अपनी समस्याओं के समाधान से वंचित न रहना पड़े।

भारत की पहली बुलेट ट्रेन का 80 प्रतिशत निर्माण पूरा, 2027 में सूरत से वापी के बीच 1 घंटे 58 मिनट में दूरी तय करेगी

नई दिल्ली, 02 नवंबर (हि.स.)।

भारत में हाई–स्पीड रेल के युग की शुरुआत जल्द होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई–अहमदाबाद हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर पर बन रही देश की पहली बुलेट ट्रेन का एक प्रमोशनल वीडियो साझा किया है। 11 सेकंड के इस वीडियो में कमिंग सून, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण और स्टे ट्यून्ड जैसे संदेशों के साथ ट्रेन के अंदरूनी ढांचे की झलक दिखाई गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में पुल, सुरंगें और ट्रैक बिछाने का काम तेजी से जारी है। सबसे पहले सूरत और वापी के बीच का सेक्शन अगस्त 2027 में खुलने की उम्मीद है। यह बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे 58 मिनट में तय करेगी। इस पूरे मार्ग पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि इन ट्रेनों की डिज़ाइन गति 350 किमी प्रति घंटा और परिचालन गति 320 किमी प्रति घंटा है, जो भारत की मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों (180 किमी/घंटा) से काफी अधिक है। इसमें विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों और उन्नत सिग्नलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों का इस्तेमाल



किया गया है।

एमएएचएसआर परियोजना केवल एक रूट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के हाई–स्पीड रेल नेटवर्क के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। देश भर में आगामी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए इसी परियोजना के आधार पर एक मानकीकृत टेम्पलेट विकसित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर से आगे बढ़कर पूरे देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार की योजना बना रही है। इसके तहत लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे सात नए हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की गई है।

नागर विमानन क्षेत्र के लिए नए नियम लागू करेगा केंद्र, 2027 से प्रभावी होंगे 'भारतीय वायुयान नियम'

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)।

केंद्र सरकार ने देश के नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक नया और व्यापक नियामकीय ढांचा अधिसूचित किया है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और लगभग नौ दशकों से लागू विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे। नए नियम विमानन क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें विमान पंजीकरण, एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन, विमान निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, कर्मियों के लाइसेंस और हवाईअड्डा संचालन से जुड़े विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य विमानन हितधारकों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट रूप से तय की गई हैं।

नए ढांचे के तहत विमानों के पंजीकरण और एयरवर्थनेस प्रमाणन से संबंधित नियमों को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने के मानदंड शामिल हैं कि कोई विमान संचालन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। नियम विमान डिजाइन, निर्माण मानकों, संशोधनों और मरम्मत से संबंधित स्वीकृतियों को भी कवर करते हैं।

सरकार ने विमानों के पूरे परिचालन जीवनकाल के दौरान नियमित निरीक्षण और रखरखाव को अनिवार्य बनाया है। एयरलाइंस और विमान संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान लगातार सुरक्षा मानकों का पालन करते रहें और उनकी एयरवर्थनेस बनी रहे।

नए नियमों में पायलटों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों सहित विमानन क्षेत्र के विभिन्न पेशेवरों के लिए योग्यता और लाइसेंसिंग मानकों को भी विस्तार से निर्धारित किया गया है। इसमें प्रशिक्षण, परीक्षा, अनुभव और चिकित्सीय फिटनेस संबंधी आवश्यकताओं के अलावा लाइसेंस के नवीनीकरण, निलंबन और रद्द करने की शर्तें भी शामिल हैं।

एयरलाइन संचालन से जुड़े प्रावधानों में फ्लाइट प्लानिंग, परिचालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर दिया गया है। पायलटों और केबिन क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी और विश्राम अवधि से जुड़े नियम भी शामिल किए गए हैं, ताकि थकान से जुड़े जोखिम कम हों और उड़ान सुरक्षा मजबूत हो सके।

यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में टिकट मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता शामिल है। अगले वर्ष से एयरलाइंस को टिकट की कुल कीमत के साथ उसका विस्तृत ब्योरा भी देना होगा, जिसमें बेस फेयर, कर, शुल्क, रद्दीकरण शुल्क और रिफंड नीति की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइन किराये अब भी नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की निगरानी के दायरे में रहेंगे। इसके अलावा नए नियमों में हवाईअड्डों के लाइसेंस, बुनियादी ढांचे के मानकों और परिचालन आवश्यकताओं से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।–आईएएनएस

एक और उपलब्धि की दहलीज पर विराट कोहली

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)।

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार (4 नवंबर) को होने वाले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट के पास एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। दरअसल, विराट कोहली वनडे में नंबर तीन की पोजीशन पर खेलते हुए अब तक 305 पारियों में 12,988 रन बना चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर पहले वनडे मुकाबले में विराट 12 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह इस पोजीशन पर खेलते हुए 13 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज रिकी पोंटिंग मौजूद हैं, जिन्होंने 365 पारियों में 12,662 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में किसी एक पोजीशन पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 15,310 रन बनाए हैं। विराट कोहली अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक शतक लगाने में सफल रहते हैं, तो वो लिस्ट–ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे। कोहली और सचिन ने अभी तक लिस्ट–ए क्रिकेट में 60–60 शतक लगाए हैं। कोहली का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर की क्रिकेट में शानदार रहा है।

विराट ने 36 मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 की दमदार औसत से खेलते हुए 1,897 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं। विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ 154 रनों की नाबाद पारी भी खेल चुके हैं।

इतिहास के पन्नों में 03 नवंबर : 1948 में नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया था स्वतंत्र भारत का पहला भाषण

नई दिल्ली, 02 नवम्बर (हि.स.)।

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 नवंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। यह स्वतंत्र भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में दिया गया पहला औपचारिक वक्तव्य था। अपने संबोधन में नेहरू ने विश्व शांति, अहिंसा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उपनिवेशवाद के विरोध को भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार के रूप में रेखांकित किया।

नेहरू ने कहा कि घृणा और हिंसा के सहारे स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत, आपसी समझ और सहयोग से निकालने पर जोर दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस संबोधन में कश्मीर का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। 1947–48 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद यह मामला संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन था। नेहरू ने भारत का पक्ष रखते हुए न्याय और संवाद के आधार पर विवाद के समाधान की बात कही। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हुआ था, जब नवस्वतंत्र भारत वैश्विक मंच पर अपनी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय भूमिका को स्पष्ट कर रहा था।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–644– ईसा पश्चात्–दूसरे मुस्लिम खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब की मदीना में एक फारसी गुलाम ने हत्या कर दी।

1394 – फ्रांस के सम्राट चार्ल्स षष्ठम ने यहूदियों को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया।

1493 – क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की।

1655 – इंग्लैंड और फ्रांस ने सैन्य और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

1762 – ब्रिटेन और स्पेन के बीच पेरिस की संधि हुई।

1796 – जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गये।

1838 – 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की स्थापना हुई।

1869 – कनाडा में हैमिल्टन फुटबॉल क्लब अस्तित्व में आया।

1903 – पनामा को कोलंबिया से आजादी मिली।

1911 – लुई शेवरले और विलियम सी डुरंट ने डेट्रॉयट में शेवरले मोटर कार कंपनी की शुरूआत की।

1938 – 'असम हिन्दी प्रचार समिति' नामक एक संस्था कायम की गई।

1957 सोवियत संघ ने लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान के पार पहुंची वह पहली जीवित प्राणी थी।

1958 – तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।

प्रभागीय वन अधिकारी का कार्यालय, दक्षिण अण्डमान, विम्बर्लीगंज, दूरभाष : 03192–255228

प्रेस विज्ञप्ति

F. No. 3-141/2025-NODAL/LS/246 दिनांक 30.10.2026

दिनांक 25.10.2026 को 'द डेली टेलीग्राम' में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर वर्ग 'ग' के औद्योगिक पद 'मजदूर' तथा अन्य वर्ग 'ग' के गैर–अनुसचिवीय पदों (राटमैन, ग्रेडर, सहायक सॉयर, बेल्टमैन, ऑयलर, टिम्बर रिकॉर्डर, टैलीमैन एवं ग्राइंडर) पर भर्ती के लिए अस्थायी रूप से पात्र एवं अपात्र उम्मीदवारों की सूचियाँ अपलोड की गई थीं। साथ ही, अपात्र उम्मीदवारों से दावे एवं आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की गई थीं।

अस्थायी रूप से अपात्र उम्मीदवारों से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की जाँच भर्ती विज्ञापन तथा लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है। जाँच के बाद अस्थायी रूप से पात्र एवं अपात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूचियाँ सभी संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आधिकारिक भर्ती पोर्टल https://erecruitment.andamannicobar.gov.in/ पर अपलोड कर दी गई हैं।

अस्वीकरण :– पात्र उम्मीदवारों की सूची पूरी तरह से अस्थायी है। प्रत्येक उम्मीदवार की अंतिम पात्रता का निर्धारण मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। यह सत्यापन परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद या भर्ती प्रक्रिया के किसी अन्य उचित चरण में किया जा सकता है। अस्थायी सूची में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही, प्रामाणिक या स्वीकार कर लिए गए हैं। इससे उम्मीदवार को अंतिम चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार या दावा प्राप्त नहीं होगा।

प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने दर्शाई गई श्रेणी (अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग–ST/OBC) केवल आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उम्मीदवार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत पात्र पाया गया है। इस संबंध में पात्रता की जाँच लागू सरकारी आदेशों तथा रिक्ति सूचना के संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

प्रभागीय वन अधिकारी
दक्षिण अण्डमान वन प्रभाग
नोडल अधिकारी (भर्ती), दक्षिण अण्डमान जिला

ग्राम पंचायत का कार्यालय, श्याम नगर स्वराज द्वीप, दक्षिण अण्डमान
सं 1–16/एसएनजीपी/एसजेडीपी/एएमसी/ई–निविदा/2026–27/309 दिनांक : 30.10.2026

ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के लिए ई–निविदा सूचना

प्रधान, ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप दो बोली प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करती है यानी इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों (सोसायटी/व्यक्तियों) से तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जिसमें कम से कम एक लाइनमैन/वायरमैन और एक सहायक शामिल है, जिनमें से एक के पास इलेक्ट्रिकल (2 वर्ष) में आईटीआई की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए या ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप, दक्षिण अंडमान के तहत स्ट्रीट लाइट वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए किसी भी लाइसेंसिंग बोर्ड से योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

निविदा दस्तावेज में कार्य का विवरण और दायरा, नियम और शर्तें आदि निर्धारित की गई हैं, जिन्हें यूआरएल का उपयोग करके ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.andamannicobar.gov.in में देखा जा सकता है।

निविदा की अनुसूची–

क्रम सं.	गतिविधि विवरण	अनुसूची
1	अनुमानित लागत	रु. 4,19,836.00 (चार लाख उन्नीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए मात्र)
2	बयाना धन जमा (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	रु. 8,397.00 (रुपये आठ हजार तीन सौ सतानवे मात्र) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत श्याम नगर के पक्ष में आहरित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 12 महीने के लिए वैध कॉल डिपॉजिट रसीद/बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद या ईएमडी छूट प्रमाण पत्र/दस्तावेज के रूप में।
3	ऑनलाइन प्रारंभ और बोली ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय	31/10/2026 के शाम 3.00 बजे से
4	निविदा दस्तावेज और स्ट्रीट लाइट दिशानिर्देश	निविदा दस्तावेज ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल – https://eprocure.andaman.gov.in में देखे जा सकते हैं और स्ट्रीट लाइट दिशानिर्देश ग्राम पंचायत श्याम नगर के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
5	ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	23/11/2026 के शाम 5.00 बजे तक
6	तकनीकी बोली खोलना	24/11/2026 को पूर्वाहन 10.00 बजे
7	वित्तीय/मूल्य का उद्घाटन बोली	https://eprocure.andamannicobar.gov.in के माध्यम से तकनीकी बोली के सत्यापन के बाद सूचित किया जाएगा। (वित्तीय मूल्य बोली केवल उन बोलीदाताओं से खोली जाएगी जो तकनीकी बोली के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं)
8	निविदा जमा करना	निविदा केवल https://eprocure.andamannicobar.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत/अपलोड की जानी है।
9	ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति के लिए बोली की वैधता अवधि/बोली प्रस्ताव की वैधता	खोलने की तारीख से 90 दिन।
10	निविदा खोलने का स्थान	ग्राम पंचायत का कार्यालय श्याम नगर, स्वराज द्वीप, दक्षिण अण्डमान
11	अनुबंध की अवधि	अनुबंध समझौते/कार्य आदेश पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
12	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	1. संबंधित कर्मचारियों के तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। 2. स्ट्रीट लाइट रखरखाव कार्य के लिए लगे कर्मचारियों का आदेश (अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न प्रारूप) 3. ईएमडी/ईएमडी छूट प्रमाणपत्र (एमएसएमई) 4. बोली सुरक्षा घोषणा (एमएसएमई को गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'बोली सुरक्षा घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है) (अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न प्रारूप)। 5. अनुभव (यदि बोलीदाता "अनुभव मानदंड" से छूट मांगता है, तो संबंधित श्रेणी के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप के वैध सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे और उन्हें छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी)। 6. टर्नओवर मानदंड (यदि बोलीदाता "बोलीदाता टर्नओवर" से छूट मांगने वाले बोलीदाता को संबंधित श्रेणी के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप के वैध सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और उन्हें छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी)। 7. पैन और जीएसटी पंजीकरण संख्या की प्रति। 8. तकनीकी बोली का एक सेट 9. पूर्ण बोली दस्तावेज की हस्ताक्षरित और सीलबंद प्रति

नोट :– बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें और अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए निविदा के समापन समय से https://eprocure.andamannicobar.gov.in पहले ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करें। मूल या ईएमडी छूट प्रमाण पत्र/दस्तावेज में ईएमडी को बंद होने की तारीख से पहले ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप, दक्षिण अण्डमान के कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में गिरा दिया जाना चाहिए।

बोलियां जमा करने में अंतिम समय की विफलता के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी। प्रधान, ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप, दक्षिण अंडमान को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रधान
ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, तुशनाबाद की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है। एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/एमजी/2026–27 /155

कार्य का नाम : टुशनाबाद पंचायत के अंर्तगत टुशनाबाद की रांची बस्ती में वार्ड संख्या 04 में सामुदायिक भवन का नवीनीकरण।

अनुमानित लागत : रु. 24,06,129/–, धरोहर राशि : रु. 48,123/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (08) आठ माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 09/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25547_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, आर.के.पुर, लिटिल अण्डमान की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/ 150

कार्य का नाम : आर. के. पुर ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड नम्बर 08 में आर. के. पुर में एलएटीआर से पीएमजीएसएसएस तक मेडिकल रोड के किनारे चेकर्ड टाइल्स के साथ सी सी फुटपाथ का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 45,96,950/–, धरोहर राशि : रु. 91,939/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 09/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25554_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

टैमर मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत का दबदबा

टैम्पेरे (फिनलैंड), 02 नवंबर (हि.स.)। भारतीय मुक्केबाजों ने टैमर मुक्केबाजी टूर्नामेंट–2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण, दो रजत और आठ कांस्य सहित कुल 14 पदक अपने नाम किए। भारत चार स्वर्ण पदकों के साथ प्रतियोगिता की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अरुंधति चौधरी, आरती धरियाल, अंकुशिता बोरो और पवन बर्तवाल ने स्वर्ण पदक जीते। टैम्पेरे मुक्केबाजी संघ की ओर से आयोजित यह प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता 1977 से लगातार हो रही है। इस बार इसमें भारत के 14 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया। भारतीय दल में देश की ओलंपिक भार वर्गों की गहराई के आधार पर तीसरे स्थान पर रहने वाले मुक्केबाज शामिल थे।

नौसेना के लिए बनाए जाएंगे अगली पीढ़ी के आठ कॉर्वेट, 53,866.50 करोड़ रुपये का अनुबंध

नई दिल्ली, 02 नवंबर (हि.स.)। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के आठ कॉर्वेट खरीदे जाएंगे, जिनके लिए सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने 53,866.50 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन–2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में यह अनुबंध गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ किया गया है। इनमें से पांच कॉर्वेट जीआरएसई बनाएगा, जबकि बाकी तीन कॉर्वेट का निर्माण जीएसएल करेगा।



रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह प्रोजेक्ट भारत की स्वदेशी वॉरशिप डिजाइन और कंस्ट्रक्शन क्षमताओं में एक अहम मील का पत्थर है। यह पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना खुद स्वदेशी रूप से डिजाइन करेगी और एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाएंगे। इन कॉर्वेट में एडवांस्ड मिसाइल, हथियार और सेंसर सूट जैसी आधुनिक क्षमताएं होंगी, जिससे वे हवा, सरफेस और सब–सरफेस डोमेन में मिशन कर सकेंगी।

इन जहाजों के समुद्री बेड़े में शामिल होने के बाद नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी, जैसे समुद्री ट्रेड रूट्स की सुरक्षा, एंटी–सरफेस और एंटी–सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन करना, कोस्टल डिफेंस को मज़बूत करना, लिटोरल कॉम्बैट ऑपरेशन करना और समुद्री प्रेजेंस और सर्विलांस मिशन करना। यह प्रोजेक्ट डीपीएसयू, प्राइवेट शिपयार्ड और लघु उद्योगों सहित भारतीय औद्योगिक भागीदार के बीच सहयोग मजबूत करके स्वदेशी शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम को काफ़ी बढ़ावा देगा।

इन जहाजों के निर्माण से अगले दस सालों में शिपयार्ड में लगभग 72 लाख रोजगार दिवस और लघु उद्योगों में 460 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत में निर्मित सामग्री और उपकरण, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों तथा भारतीय कौशल एवं विशेषज्ञता के उपयोग को बढ़ावा देकर यह परियोजना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 52वें एयर फोर्स वाइस चीफ का पद संभाला

नई दिल्ली, 02 नवंबर (हि.स.)। नए वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित के कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 52वें वाइस चीफ का पद संभाल लिया है। फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए एयर मार्शल के पास अपने तीन दशकों से अधिक के करियर में मिग–21, मिग–23, मिग–27, जगुआर और सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमानों पर 3200 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वालों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।



वायु सेना में 11 जून 1988 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और वायु सेना अकादमी, डुंडीगुल के पूर्व छात्र हैं। वह एडवांस्ड कमांड एंड स्टाफ कोर्स, यूनाइटेड किंगडम और नेशनल डिफेंस कॉलेज, बांग्लादेश के पूर्व छात्र भी हैं। उनके पास रक्षा और सामरिक अध्ययन में तीन स्नातकोत्तर डिग्री हैं। अपने तीन दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने भारतीय वायु सेना के विभिन्न लड़ाकू विमान उड़ाए हैं, जिनमें मिग–21, मिग–23, मिग–27, जगुआर और एसयू–30 एमकेआई के विभिन्न प्रकार शामिल हैं। उनके पास विभिन्न लड़ाकू जेट विमानों पर 3200 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है और उन्होंने कई कमांड और स्टाफ नियुक्तियां की हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वह एक बेहद अनुभवी लड़ाकू पायलट और एक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग इंस्ट्रक्टर और परीक्षक हैं। अपने परिचालन कार्यकाल में वह नंबर 222 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के कमांडेंट रह चुके हैं। उन्होंने एक फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन और एयर ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर एयर फोर्स स्टेशन बरेली की कमान संभाली है। उन्हें 2018 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2008 में वायु सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। एयर कमोडोर के तौर पर उन्होंने पूर्वी वायु कमान में एयर–1 के तौर पर और बाद में एयर हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में एयर कमोडोर (एयर स्टाफ इंस्पेक्शन) के तौर पर काम किया।

महिलाओं की खेलों में भागीदारी व नेतृत्व को मजबूत करने पर मंथन करेगा महिला आयोग

नई दिल्ली, 02 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) खेलों में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, समानता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को विज्ञान भवन में 'खेल शक्तिः महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परामर्श' का आयोजन करेगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय परामर्श में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी और उनके कल्याण, सुरक्षा तथा पेशेवर विकास के लिए प्रभावी उपायों पर सुझाव तैयार किए जाएंगे। आयोग के बयान के मुताबिक कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी।

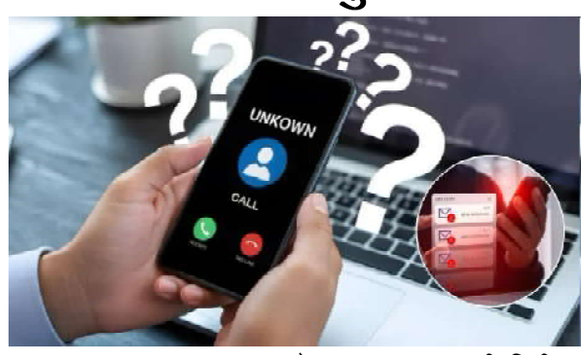
राष्ट्रीय परामर्श में खिलाड़ी, ओलंपियन, खेल प्रशासक, प्रशिक्षक, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि, भारतीय खेल प्राधिकरण, चिकित्सा एवं खेल विज्ञान विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और महिला खिलाड़ियों के अभिभावक हिस्सा लेंगे। विभिन्न हितधारक इन मुद्दों पर चर्चा कर व्यावहारिक और प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

परामर्श के दौरान तीन व्यापक विषयों पर चर्चा होगी। इनमें महिलाओं की खेलों में भागीदारी का विस्तार और जमीनी स्तर पर खेल व्यवस्था को मजबूत करना, सुरक्षित एवं स्वस्थ खेल वातावरण सुनिश्चित करना तथा समानता, करियर की निरंतरता और खेलों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना शामिल है।

---

1 नवम्बर से देशभर में कॉलर का नाम दिखाने वाली नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 02 नवम्बर। क्या आपके मोबाइल पर भी अनजान नंबरों से बार–बार कॉल आती हैं? कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि फोन करने वाला कौन है और कॉल उठाना सुरक्षित होगा या नहीं। लेकिन अब इस परेशानी से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। दरअसल, 1 नवंबर 2026 से देश में कॉलर का नाम दिखाने वाली नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके तहत मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का रजिस्टर्ड नाम भी दिखाई दे सकेगा।



दूरसंचार विभाग ने देश की टेलीकॉम कंपनियों को Calling Name Presentation (CNAP) सर्विस शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था में Airtel, Jio, Vodafone Idea और BSNL जैसे ऑपरेटर्स को 4जी और इससे ऊपर के नेटवर्क पर यह सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ऐसे में आने वाले समय में अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करना पहले से आसान हो सकता है।

सर्विस शुरू होने के बाद जब भी किसी अनजान भारतीय मोबाइल नंबर से कॉल आएगी, तो फोन की स्क्रीन पर केवल मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का रजिस्टर्ड नाम भी दिखाई दे सकता है। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें कौन फोन कर रहा है।

इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को Truecaller जैसे किसी थर्ड पार्टी एप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यानी बिना किसी अतिरिक्त एप या अलग से सर्विस एक्टिवेट किए ही कॉलर की पहचान करने की सुविधा मिल सकेगी।

CNAP यानी Calling Name Presentation सर्विस टेलीकॉम कंपनियों के डेटाबेस पर काम करेगी। इसके तहत मोबाइल ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर और उनके रजिस्टर्ड नाम से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई व्यक्ति दूसरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा, तो कॉल रिसीव करने वाले ऑपरेटर को कॉल करने वाले नंबर से जुड़ा नाम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यह जानकारी रिसीवर के मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगी।

हालांकि, अगर कॉल करने वाले का नंबर पहले से आपके फोन में सेव है, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दर्ज नाम ही दिखाई देगा। इस नई व्यवस्था में कुछ खास नियम भी रखे गए हैं। अगर किसी दूसरे देश से आपके मोबाइल पर कॉल आती है, तो स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखने के बजाय International Call लिखा दिखाई देगा।

इसके अलावा जिन मोबाइल यूजर्स ने Calling Line Identification Restriction (CLIR) सर्विस ली हुई है, उनका नाम दूसरे व्यक्ति की स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। इस सर्विस के जरिए कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान छिपा सकता है।

यहां यूजर्स के लिए एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। 1 नवंबर 2026 से निर्देश लागू होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन देश के सभी मोबाइल फोन पर यह सुविधा एक साथ शुरू हो जाएगी। इसका लाभ मिलने का समय टेलीकॉम कंपनियों के तकनीकी इंतजाम और सर्विस रोलआउट पर निर्भर करेगा।

ऐसे में आने वाले समय में CNAP सर्विस अनजान कॉल की पहचान करने में मददगार साबित हो सकती है। इससे फर्जी कॉल और अनचाही कॉल से परेशान लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।